receipt of grants from Central Government are required to follow the prescribed reservation policy in terms of the existing instructions. The names of such autonomous bodies are not centrally maintained. However, no instance of non-compliance with the 40 point roster by any Central Government Office/ Autonomous Body has come to the notice of the Government. As far as the question of qualifing service for promotion is concerned, such service is prescribed interms of the relevant recruitment rules governing different posts/services in the concerned Central Government Office/Autonomous Body.

CBI Raids Against Telecom Officers

4343. SHRI SATISH PRADHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the CBI has raided houses of telecom officers, as reproted in the Maharashtra Times of 20th February, 1997;

(b) if so, where and what is the number of such officers;

(c) the details of places where these raids have been conducted; and

(d) what are the findings?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS. (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) Yes, Sir.

(b) The residential/office premises of 3 telecom Officers and one private contractor were raided on 31.1.1997 at Mumbai, Nagpur, Goa and Delhi.

(c) The raids were conducted:

1. at the residence of the then General Manager (Retd), Goa Telecom, Panaji, Goa at Type-E Quarters, Telephone Exchange Building, Chambur, Mumbai.
2. at the residence and office of the then Director, Finance & Accounts, Goa Telecom, Panaji, now at Nagpur at Qtr. No. 9, Type V, Sanchar Vihar, Nagpur and at the Office at Zero Miles, Nagpur.
3. at the residence of the Deputy General manager, Deptt. of Telecom, Panaji at E-I-I General Pool, PWD Quarters, Porvorim, Panaji Goa and at the office premises at Telecom office 18th June Road, Panaji.

During the house search at Type-E Quarters, Chambur, Mumbai, apart from incriminating documents, a cash amount of Rs. 4,02,000/- were seized for which the officer (retired) could not give any satisfactory explanation. During the search, 4 locker keys were seized. The lockers were searched subsequently and cash of Rs. 1,44,500/- has been seized from locker No. 180 in Bank of India, Janpath, New Delhi. Cash of Rs. 6 Lakhs has been seized from locker No. 1007 of Canara Bank, Chembur Main Branch, Mumbai. Cash of Rs. 1 lakh was seized from Locker No. 175 in SBI, Konkan Bhavan, Commercial Banking Division, New Delhi. Apart from 650 gm of gold jewellery seized from the residence of the retired officer, gold jewellery weighing more than 1 kg was found in Locker No. 151 of Bank of India, Chambur, Mumbai.

Besides this, documents pertaining to one Maruti 800 Car, one Maruti Van, 2 Scooters and deposits in banks and investments in FDRs, NSCs, Kisan Vikas Patra, Indira Vikas Patra and Shares of various companies worth Rs. 30 lakhs approximately have been seized. Documents pertaining to two flats and one business premises in Bombay, one flat in Delhi and one flat in Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) has also been seized.

Three files have been seized at the residence of one of the officers.

Three floppies and 3 diaries have been seized from the residence of another one of the officers.

सांसदों और विधायकों के साथ कार्य-व्यवहार करने संबंधी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों में संशोधन

4344. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सांसदों और विधायकों के साथ कार्य-व्यवहार करने के संबंध में सरकारी अधिकारियों के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों/अनुदेशों में संशोधन करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन संशोधनों को अन्तिम रूप देने से पहले निर्वाचित प्रतिनिधियों के विचार जानना चाहेगी;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालसुब्रमणियन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की छंटनी/अनिवार्य सेवानिवृत्ति

4345. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त केन्द्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छंटनी कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए है;

(ग) अखिल भारतीय सेवाओं के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भ्रष्टाचार एवं गंभीर अनियमितताओं में लिप्त और अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन पाया गया है; और

(घ) इन अधिकारियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालसुब्रमणियन): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, जिनकी सत्यनिष्ठा संदेहास्पद है और साथ ही जो अक्षम हो चुके है, उनकी छंटनी करने के उद्देश्य से संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत उनके सेवा रिकार्डों की पुनरीक्षा इस विचार से की जाती है कि क्या उन्हें समय-पूर्व सेवानिवृत्त किया जाए अथवा निर्धारित आयु (50/55 वर्ष) प्राप्त करने या 30 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवा में रखा जाए। यह एक नियमित तथा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति भी सेवा-नियमों के अंतर्गत निर्धारित, एक भारी शास्ति है तथा यह कदाचार सिद्ध हो जाने वालों मामलों में लगाई जाती है।

(ग) तथा (घ) एक विवरण संलग्न है।

अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा जिन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	सेवा का नाम	अभियोग	की गई कार्रवाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ए० एन० बताबयाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र)	भारतीय प्रशासनिक सेवा	बम्बई में ऊंची कीमत वाले प्लाट को बेचना	24.2.1994 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति